भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3565
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

विद्यालय में बिताए जाने वाले अनुमानित वर्ष

†3565. **श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस में विद्यालय के अनुमानित वर्ष 15 हैं, जबकि भारत में यह 13.37 वर्ष हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि रूस में श्रम उत्पादकता यूएस $44.31 प्रति घंटा है, जबकि भारत में यह मात्र यूएस $10.68 है;
(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विद्यालय के अनुमानित वर्षों और श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और भारत कब तक विद्यालय के वर्षों और श्रम उत्पादकता के मामले में रूस के आंकड़ों तक पहुँच जाएगा; और
(घ) तीव्र आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी में उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा, विशेषकर विद्यालय शिक्षा के साथ-साथ रोजगार-उन्मुख कौशल विकास में निवेश में कितनी बढ़ोतरी अपेक्षित है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): विद्यालय के अनुमानित वर्षों, श्रम उत्पादकता और श्रमिकों के कौशल में वृद्धि एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। सरकार यह मानती है कि अधिगम परिणामों में सुधार, स्कूल छोड़ने वालों को कम करना और पाठ्यक्रम अंतराल को दूर करना रोजगार क्षमता और कार्यबल की तैयारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में शिक्षार्थियों को उच्चतर शिक्षा, रोजगार और आजीवन अधिगम के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दक्षताओं से लैस करने के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान, योग्यता-आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, बहु-विषयक शिक्षा और कौशल शिक्षा के अधिक एकीकरण के माध्यम से शिक्षा प्रणाली के समग्र परिवर्तन की परिकल्पना की गई है।

स्कूल स्तर पर, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कौशल शिक्षा को शिक्षा के एक नियमित घटक के रूप में एकीकृत किया गया है। संप्रेषण, स्व-प्रबंधन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), उद्यमिता और हरित कौशल सहित रोजगार योग्यता कौशल को बढ़ाने के लिए कक्षा 9-12 के छात्रों को एनएसक्यूएफ-अनुकूलित कौशल पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। एनईपी 2020 के अनुरूप, कक्षा 6-8 के छात्रों को बैगलेस डेज, स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप और अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से पूर्व-व्यावसायिक अनुभव प्रदान किया जाता है। सरकार ने दीक्षा, स्वयम, स्वयम प्रभा और वर्चुअल स्किल लेबोरेटरीज जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल लर्निंग को भी बढ़ावा दिया है, जबकि पीएम श्री स्कूल अनुभवात्मक शिक्षा, डिजिटल अवसंरचना और कौशल विकास पर बल देते हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाना है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ीकरण करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उन्नयन तथा संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना करना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुकूलित छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें और नि:शुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है।

वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक देश के केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है:

शिक्षा मंत्रालय का बजट (रूपए करोड़ में)			
वित्तीय वर्ष	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग बजट अनुमान परिव्यय	उच्चतर शिक्षा विभाग बजट अनुमान परिव्यय	शिक्षा मंत्रालय के बजट अनुमान परिव्यय
2022-23	63449	40828	104278
2023-24	68805	44095	112899
2024-25	73498	47620	121118
2025-26	78572	50077	128649
2026-27	83562	55727	139289

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

******